Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X (Print), Impact Factor: (Cosmos: 7.866 & I2OR: 5.675) Volume 16, No. 01(II), January-March, 2026, pp. 134-137

रीवा जिले में वनोपज आधारित रोजगार सृजन एवं आय वृद्धि के अवसरों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

शिवानी सिंह[1*] एवं डॉ. मनीष कुमार शुक्ला[2]

[1]शोधार्थी वाणिज्य, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह, महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश।
[2]प्राध्यापक वाणिज्य विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह, महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश।

[*]Corresponding Author: pariharshivanisingh771@gmail.com

***Citation**: सिंह, शिवानी एवं शुक्ला, मनीष (2026). रीवा जिले में वनोपज आधारित रोजगार सृजन एवं आय वृद्धि के अवसरों का विश्लेषणात्मक अध्ययन. Journal of Modern Management & Entrepreneurship, 16(01(II)), 134–137.*

सार

रीवा जिला, जो मध्यप्रदेश के विंध्य क्षेत्र का एक प्रमुख भू–भाग है, प्राकृतिक संसाधनों विशेषकर वनोपज की दृष्टि से समृद्ध रहा है। वनोपज जैसे तेंदूपत्ता, महुआ, हर्रा, बहेरा, आंवला आदि न केवल पारंपरिक आजीविका का आधार हैं, बल्कि वर्तमान में इनके वाणिज्यिक उपयोग ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य रीवा जिले में वनोपज आधारित गतिविधियों के माध्यम से रोजगार सृजन एवं आय वृद्धि के अवसरों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। विपणन तंत्र की कमजोरियाँ, मध्यस्थों का हस्तक्षेप तथा तकनीकी ज्ञान का अभाव इस क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि उचित नीति समर्थन, प्रशिक्षण एवं अवसंरचना का विकास किया जाए तो वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था न केवल रोजगार सृजन को बढ़ावा दे सकती है, बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

***शब्दकोश:** वनोपज, रोजगार सृजन, आय वृद्धि, लघु वनोपज, वाणिज्यिकरण, रीवा जिला, ग्रामीण अर्थव्यवस्था।*

प्रस्तावना

भारत की अर्थव्यवस्था में वन संसाधनों का ऐतिहासिक एवं समकालीन महत्व अत्यंत व्यापक रहा है। विशेष रूप से मध्यप्रदेश, जिसे "भारत का हृदय प्रदेश" कहा जाता है, वन संपदा की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। रीवा जिला, जो विंध्य क्षेत्र में स्थित है, अपनी भौगोलिक संरचना एवं प्राकृतिक संसाधनों के कारण विविध प्रकार की वनोपज का प्रमुख स्रोत रहा है। यहाँ के वन क्षेत्र न केवल पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में सहायक हैं, बल्कि स्थानीय समुदायों के जीवनयापन का आधार भी हैं।

वनोपज, विशेषकर लघु वनोपज (Non & Timber Forest Produce & NTFPs), जैसे तेंदूपत्ता, महुआ, हर्रा, बहेरा, आंवला आदि ग्रामीण एवं आदिवासी समुदायों की आय का प्रमुख साधन हैं। परंपरागत रूप से इनका उपयोग घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता था, किंतु वर्तमान में इनके वाणिज्यिक उपयोग ने इन्हें आय सृजन के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में स्थापित कर दिया है।

[*] Copyright © 2026 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.

रीवा जिले में वनोपज आधारित गतिविधियाँ जैसे– संग्रहण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग एवं विपणन, रोजगार के विविध अवसर प्रदान करती हैं। विशेष रूप से तेंदूपत्ता संग्रहण के दौरान हजारों ग्रामीण परिवारों को मौसमी रोजगार प्राप्त होता है। इसी प्रकार, महुआ एवं अन्य वनोपजों का प्रसंस्करण स्थानीय स्तर पर लघु उद्योगों को बढ़ावा देता है। वर्तमान आर्थिक परिप्रेक्ष्य में वनोपज का वाणिज्यिकरण ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। यदि इन संसाधनों का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित उपयोग किया जाए तो यह न केवल रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा, बल्कि क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में भी सहायक सिद्ध होगा।

हालांकि इस क्षेत्र में कई चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं, जैसे– अपर्याप्त बाजार सूचना, मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता का अभाव, मध्यस्थों का हस्तक्षेप एवं प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी। इन समस्याओं के कारण वनोपज संग्रहकर्ताओं को उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता। इस संबंध में सरकारी योजनाएँ एवं सहकारी संस्थाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। यदि इन संस्थाओं के माध्यम से संगठित विपणन, प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाए तो वनोपज आधारित गतिविधियों को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि वनोपज आधारित रोजगार सृजन एवं आय वृद्धि के अवसरों का वैज्ञानिक एवं वाणिज्यिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जाए, जिससे नीति निर्माण एवं क्षेत्रीय विकास में सहायक निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकें।

शोध का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य रीवा जिले में उपलब्ध वनोपज संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग के माध्यम से रोजगार सृजन एवं आय वृद्धि की संभावनाओं का विश्लेषण करना है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, ग्रामीण एवं आदिवासी समुदायों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने हेतु वनोपज एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरकर सामने आया है। इस अध्ययन के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार वनोपज आधारित गतिविधियाँ स्थानीय स्तर पर आर्थिक अवसरों का सृजन कर रही हैं तथा इनसे प्राप्त आय में वृद्धि किस सीमा तक संभव है। इस प्रकार शोध अध्ययन से संबंधित कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

- रीवा जिले में वनोपज आधारित रोजगार के स्वरूप एवं संरचना का विश्लेषण करना।
- वनोपज से प्राप्त आय के स्तर एवं उसमें वृद्धि की संभावनाओं का अध्ययन करना।
- वनोपज के वाणिज्यिकरण में बाधाओं एवं सुधारात्मक उपायों का मूल्यांकन करना।

उक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए शोध पत्र को वास्तविक मानकों के अनुरूप पूर्ण करने का सार्थक प्रयास किया गया है।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध पत्र में मुख्यतः द्वितीयक समंकों का उपयोग किया गया है। अध्ययन के लिए मध्यप्रदेश शासन के वन विभाग की वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक सर्वेक्षण, लघु वनोपज संघ की रिपोर्ट्स तथा विभिन्न शोध पत्रों एवं पुस्तकों का संदर्भ लिया गया है। द्वितीयक आंकड़ों के विश्लेषण हेतु तुलनात्मक एवं व्याख्यात्मक विधियों का प्रयोग किया गया है। इस अध्ययन में वनोपज आधारित गतिविधियों के आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न वर्षों के आंकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक दृष्टिकोण से मूल्य संवर्धन, विपणन तंत्र एवं आय वितरण की संरचना का भी अध्ययन किया गया है। समंकों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त समंकों का परस्पर सत्यापन किया गया है। अध्ययन में वर्णनात्मकएवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का समन्वित उपयोग किया गया है, जिससे निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय एवं प्रासंगिक बन सके।

विश्लेषण

रीवा जिले में वनोपज आधारित गतिविधियाँ रोजगार सृजन के महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरकर सामने आई हैं। विशेष रूप से तेंदूपत्ता संग्रहण, महुआ प्रसंस्करण एवं अन्य लघु वनोपजों का व्यापार ग्रामीण क्षेत्रों में आय का प्रमुख स्रोत है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष हजारों परिवार इन गतिविधियों में संलग्न होकर मौसमी एवं स्थायी रोजगार प्राप्त करते हैं।वनोपज आधारित रोजगार का एक प्रमुख पहलू यह है कि इसमें पूंजी निवेश अपेक्षाकृत कम होता है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी इसमें आसानी से भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त, महिलाओं की भागीदारी भी इस क्षेत्र में उल्लेखनीय है, जो सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है।वाणिज्यिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वनोपज का मूल्य संवर्धन आय वृद्धि का एक महत्वपूर्ण साधन है। उदाहरण के लिए, कच्चे महुआ के स्थान पर उसका प्रसंस्कृत उत्पाद अधिक मूल्य पर बाजार में बिकता है। इसी प्रकार, आंवला एवं हर्रा जैसे उत्पादों का औषधीय एवं औद्योगिक उपयोग उनके बाजार मूल्य को बढ़ाता है। विपणन तंत्र की कमजोरी एवं मध्यस्थों की भूमिका के कारण वनोपज संग्रहकर्ताओं को उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त, तकनीकी ज्ञान एवं प्रशिक्षण के अभाव में मूल्य संवर्धन की संभावनाएँ सीमित रह जाती हैं। सरकारी हस्तक्षेप एवं सहकारी संस्थाओं के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। यदि संगठित विपणन, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) एवं प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर ध्यान दिया जाए, तो वनोपज आधारित आय में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है।

इस प्रकार शोध क्षेत्र में वनोपज आधारित योजनाओं का आर्थिक प्रभाव से संबंधित विवरण सारणी 01 में प्रस्तुत किया गया है, जो इस प्रकार है –

सारणी 1: रीवा जिले में वनोपज आधारित योजनाओं का आर्थिक प्रभाव संबंधी विवरण

क्रमांक	योजनाओं / गतिविधियों का विवरण	आर्थिक प्रभाव (%)
1.	तेंदूपत्ता संग्रहण योजना	35%
2.	महुआ प्रसंस्करण एवं विपण	20%
3.	आंवला एवं औषधीय वनोपज व्यापार	15%
4.	वन आधारित लघु उद्योग	18%
5.	सहकारी विपणन तंत्र	12%
	योग	100%

स्रोत – मध्यप्रदेश शासन के वन विभाग, लघु वनोपज संघ, आर्थिक सर्वेक्षण एवं जिला उद्योग केंद्र की द्वितीयक रिपोर्टों के संकलित आंकड़ों पर आधारित, वर्ष 2024–2025

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि रीवा जिले में वनोपज आधारित गतिविधियों में तेंदूपत्ता संग्रहण योजना का आर्थिक प्रभाव सर्वाधिक (35%) है, जो रोजगार सृजन का प्रमुख स्रोत है। महुआ प्रसंस्करण एवं विपणन (20%) भी आय वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वन आधारित लघु उद्योग (18%) एवं औषधीय वनोपज व्यापार (15%) यह दर्शाते हैं कि मूल्य संवर्धन एवं विविधीकरण के माध्यम से आय के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। सहकारी विपणन तंत्र (12%) का योगदान अपेक्षाकृत कम है, जो इस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता को इंगित करता है।

शोध समस्या एवं सुझाव

रीवा जिले में वनोपज आधारित रोजगार सृजन एवं आय वृद्धि की संभावनाएँ होने के बावजूद इस क्षेत्र में कई संरचनात्मक एवं वाणिज्यिक समस्याएँ विद्यमान हैं। प्रमुख समस्या यह है कि वनोपज संग्रहण एवं विपणन प्रक्रिया में मध्यस्थों का अत्यधिक हस्तक्षेप होता है, जिसके कारण वास्तविक संग्रहकर्ताओं को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त, बाजार संबंधी जानकारी का अभाव, मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता की कमी तथा संगठित विपणन तंत्र का अभाव इस क्षेत्र की प्रमुख बाधाएँ हैं। तकनीकी ज्ञान एवं

प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी के कारण वनोपज का मूल्य संवर्धन नहीं हो पाता, जिससे आय वृद्धि की संभावनाएँ सीमित रह जाती हैं।

इन समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक है कि सहकारी समितियों एवं शासकीय संस्थाओं के माध्यम से वनोपज के संगठित विपणन को प्रोत्साहित किया जाए। संग्रहकर्ताओं को प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर मूल्य संवर्धन की दिशा में सशक्त किया जाना चाहिए। साथ ही, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की प्रभावी व्यवस्था एवं बाजार सूचना प्रणाली का विकास किया जाना आवश्यक है। यदि इन सुझावों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, तो वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था को अधिक सुदृढ़ एवं लाभकारी बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष

अध्ययन के निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि रीवा जिले में वनोपज आधारित गतिविधियाँ रोजगार सृजन एवं आय वृद्धि के महत्वपूर्ण साधन के रूप में स्थापित हो चुकी हैं। विशेष रूप से लघु वनोपज का वाणिज्यिक उपयोग ग्रामीण एवं आदिवासी समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण में सहायक सिद्ध हो रहा है। हालांकि, इस क्षेत्र में अभी भी अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं, जैसेकृविपणन तंत्र की कमजोरी, तकनीकी ज्ञान का अभाव एवं मध्यस्थों का हस्तक्षेप। इन समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक है कि सरकार एवं संबंधित संस्थाएँ संगठित प्रयास करें। यदि वनोपज के मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण एवं विपणन पर विशेष ध्यान दिया जाए, तो यह क्षेत्र न केवल रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा, बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, आर.के., वन संसाधन प्रबंधन, जयपुर, 2018, पृ. 112।
2. सिंह, ए.के., भारतीय वन अर्थव्यवस्था, नई दिल्ली, 2019, पृ. 87।
3. गुप्ता, एस.पी., लघु वनोपज एवं ग्रामीण विकास, भोपाल, 2020, पृ. 134।
4. वर्मा, एम.एल., थ्वतमेज म्बवदवउल पद प्दकपं, नई दिल्ली, 2021, पृ. 156।
5. मध्यप्रदेश शासन, आर्थिक सर्वेक्षण, भोपाल, 2022।
6. लघु वनोपज संघ, वार्षिक प्रतिवेदन, 2023।
7. वन विभाग, मध्यप्रदेश, वार्षिक रिपोर्ट, 2024।

❑❑❑